अरबों के सीएसआर फंड पर सरकार का फोकस

भूमि पूजन समारोह : सामाजिक जिम्मेदारी उठाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश धरातल पर उतरेगा। औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों से उद्योगों को जोड़ने की पहल भी होगी। समारोह के दूसरे दिन 20 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्योग जगत के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) अधिकारियों के साथ सरकार के छह विभाग संवाद करेंगे।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम के तहत कंपनियों को वर्तमान वित्त वर्ष से पहले के तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर में खर्च करना अनिवार्य है। बड़ी संख्या में कंपनियां सामाजिक सरोकारों में करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। प्रदेश सरकार सीएसआर के तहत सामाजिक कार्य करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े

20 को उद्योगों के सीएसआर प्रमुखों से छह विभागों के अफसर करेंगे संवाद

अधिकारी कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों के साथ बात करेंगे।

सीएसआर सेमिनार की रूपरेखा तैयार हो गई है। बड़ी कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों को प्रदेश सरकार के विभाग अपने कामकाज के बारे में बताएंगे। सामाजिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सीएसआर फंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दुग्धशाला विकास विभाग और खेल विभाग सीएसआर से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे।

यूपी में पांच साल में चार गुना बढ़ा सीएसआर फंड

लखनऊ। सीएसआर के मामले में यूपी देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। दस साल पहले यूपी सीएसआर फंड प्राप्त करने की सूची में देश का 12वां राज्य था। वर्ष 2017-18 में यूपी में सीएसआर के जरिये 435 करोड़ खर्च किए गए थे। वर्ष 21-22 में ये बढ़कर 1321 करोड़ हो गया। 22-23 में 1500 करोड़ से ज्यादा सीएसआर मद में आए। जबकि वर्ष 2015 में महज 148 करोड़ रुपये सीएसआर में खर्च किए गए थे। सीएसआर फंड का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत, सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। 5229 करोड़ के साथ महाराष्ट्र पहले, 1761 करोड़ के साथ कर्नाटक दूसरे, 1554 करोड़ के साथ गुजरात तीसरे और 1371 करोड़ के साथ तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। ब्यूरो